SANDHYA TIMES, Delhi, 26.5.2025
Page No. 2, Size:(12.70)cms X (17.38)cms.

TVC द्वारा सर्वे पूरा होने तक उजाड़ीकरण पर रोक लगाने की गुहार : अनिल बक्शी

उजाड़ीकरण का दंश झेल रहे दिल्ली में स्ट्रीट वेंडर्स

Suraj.Singh@timesofindia.com

■ **आज 26 मई** को 'इंटरनैशनल हॉकर्स डे' है। यह दिन सड़क विक्रेताओं के अधिकारों, उनके जीवन और आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे मुद्दों और उनके कार्य के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। मगर, दिल्ली के रेहड़ी-पटरी, स्ट्रीट वेंडर्स, फेरी, खोमचा, बॉडी हॉकर्स,

साप्ताहिक बाजारों में पसीना बहाने वाले विक्रेताओं की स्थिति अच्छी नहीं है। नैशनल हॉकर फेडरेशन के राष्ट्रीय सचिव **अनिल बक्शी** ने बताया कि दिल्ली सरकार ने अतिक्रमण, स्वच्छ दिल्ली और विकसित दिल्ली के नाम पर उजाड़ीकरण अभियान तेज कर रखा है। रेहड़ी-पटरी वालों के मौलिक अधिकारों को रोजाना MCD, PWD, NDMC, पुलिस, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, ट्रैफिक पुलिस, DDA और अन्य विभागों द्वारा छीना जा रहा है। अब आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लिए परिवार का पेट पालना मुश्किल हो गया है। सभी को एक साथ आकर अपने रोजगार और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना होगा। आज सुबह LG हाउस पर हॉकर्स ने इकट्ठा होकर अपने हक की आवाज उठाई।

केंद्र और राज्य सरकार से गुहार लगाई कि पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के तहत रेहड़ी-पटरी वालों के अधिकारों का सम्मान किया जाए। जब तक टाउन वेंडिंग कमिटी (TVC) द्वारा दिल्ली में पूरी तरह सर्वे नहीं हो जाता, तब तक उजाड़ीकरण पर फौरन रोक लगाई जाए।

6 साल में सिर्फ 77 हजार वेंडर्स का सर्वे

अनिल बक्शी ने बताया कि संसद ने पथ विक्रेता जीविका सुरक्षा एवं पथ विक्रय विनियमन अधिनियम 2014 पारित किया। इसमें तय हुआ कि सभी राज्य सरकारें टाउन वेंडिंग कमिटी (TVC) का गठन करेंगी। ये सर्वे के बाद अधिकृत पथ विक्रेताओं को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग (CoV) जारी करेंगी। दिल्ली में भी पिछली सरकार ने TVC से सर्वे प्रक्रिया शुरू कराई। मगर, 6 साल में सिर्फ 77 हजार स्ट्रीट वेंडर्स का ही सर्वे हो पाया, जिन्हें CoV भी मिला। इसमें भी एक अव्यवहारिक शर्त है, जिसमें एक वेंडर एक स्थान पर 30 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकता। वे गैर-कानूनी है। कोई आदमी 20 साल से ठिया लगाकर बैठा है, तो उसे भी मोबाइल वेंडर बना दिया। दिल्ली में करीब 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स है। अब जिनका सर्वे हो भी गया, उनका भी शोषण सरकारी एजेंसियां कर रही है। अधिनियम का गंभीरता से पालन नहीं हो रहा।

'अतिक्रमणकारी नहीं हैं स्ट्रीट वेंडर्स'

स्ट्रीट वेंडर्स अतिक्रमणकारी नहीं है। वे उद्यमी हैं। शहर की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देते हैं। अब समय आ गया है कि प्रशासन रेहड़ी-पटरी, वेंडर, हॉकर, खोमचे वालों को मान्यता दे। मनमानी बेदखली अभियान पर रोक लगनी चाहिए। NASVI ने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के सख्त अनुपालन, टाउन वेंडिंग कमिटियों के गठन और पुनर्वास की उचित व्यवस्था होने तक उजाड़ीकरण एक्शन को रोकने की मांग की है।

-अरबिंद सिंह, राष्ट्रीय समन्वयक, नैशनल असोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (NASVI)

NHRC से भी शिकायत

अरबिंद सिंह ने बताया कि इस संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) में रजिस्ट्रार (कानून) जोगिंदर सिंह से भी पिछले हफ्ते मुलाकात की। उन्हें बताया कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का निरंतर उल्लंघन हो रहा है। कानूनी सुरक्षा के बावजूद स्ट्रीट वेंडर्स को उत्पीड़न और विस्थापन का सामना करना पड़ रहा है। जोगिंदर सिंह ने मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने प्रत्येक वेंडर की शिकायतों का विवरण मांगा है, ताकि कंप्लेंट दर्ज कर एक्शन शुरू हो सके।

PIONEER, Hyderabad, 27.5.2025
Page No. 4, Size:(16.52)cms X (19.08)cms.

Hand over bodies of Maoists to kin: Rights activists

PNS ■ WARANGAL

Even though five days have passed since the encounter in Chhattisgarh, the police have not yet handed over the bodies of the members of the outlawed Communist Party of India-Maoist, better known as the Maoist party, to their relatives. Relatives and friends of the Maoists killed in the encounter protested in Chintagattu under Hasanparthy mandal in Warangal.

Rights activists participated in the protest demanding immediate release of the Maoists' bodies.

One of the Maoists named Burra Rakesh, hailed from Chintagattu village was killed in the encounter.

Rakesh's mother, Swaroop, stated that if the police failed to hand over her son's body, the entire family would commit collective suicide.

There is serious concern over the refusal to hand over the bodies of those killed during the operation on May 21 in the Abujhmad area of Chhattisgarh. Some of those Maoists killed belonged to Telangana and Andhra Pradesh.

Villagers and rights activists staging a protest over the failure of the officials to hand over the body of Maoist Burra Rakesh, in Chintagattu village in the Warangal district

Despite clear legal and moral responsibilities to preserve the bodies with respect, there were allegations that the bodies were not kept in cold storage.

Families have already assured senior advocates that they are willing to comply with any conditions to conduct peaceful last rites. Still, the bodies have not been released.

The National Human Rights Commission (NHRC) issued clear guidelines in 2020 on respectful treatment of deceased persons, including timely cremation or burial, proper preservation, and dignified transport, the rights activists said.

AAJ, Bareily, 27.5.2025
Page No. 03, Size:(9.41)cms X (7.14)cms.

थाने में पिटाई से आहत सलमान की खुदकुशी का मामला

एनएचआरसी ने अपनाया सख्त रवैया, दर्ज हुआ केस, पुलिस व प्रशासन से जवाब- तलब

बरेली (आज समाचार सेवा)। क्योलड़िया थाना क्षेत्र में पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर फांसी लगाकर जान देने वाले 18 वर्षीय युवक सलमान की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सख्त रुख अपनाया है। समाजसेवी महेश पांडेय की शिकायत पर आयोग ने पुलिस और जिला प्रशासन से जवाब तलब किया है। आयोग ने इसे प्रथम दृष्टया गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन माना है। आपको बता दें कि सलमान पर आरोप था कि उसने एक लड़की को भगाने में अपने दोस्त की मदद की थी। उसका जुर्म केवल इतना ही था कि उसने अपने मोबाइल से एक लड़की से अपने दोस्त की बात कराई थी। इसके बाद पुलिस ने उसे बार-बार थाने बुलाया और बेरहमी से पीटा। परिजनों के मुताबिक, पुलिस उसे थर्ड डिग्री देती रही। उसे जेल भेजने की धमकी दी गई। दबाव इतना बढ़ा कि एक मई की शाम सलमान ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। सलमान के पिता अशफाक ने बताया, है कि मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए पहले 6,500 और फिर 50,000 रुपए की रिश्वत भी दी। इसके लिए उधार लेना पड़ा। मगर पुलिस वालों ने मेरे बेटे को फिर भी नहीं छोड़ा। मारते रहे, धमकाते रहे... यहां तक कह दिया कि इसकी हड्डियां तोड़ देंगे। परिजन बताते हैं कि सलमान पुलिस की पिटाई के बाद तीन दिन तक चुपचाप बैठा रहा। वह गहरे सदमे में था। किसी से बात नहीं करता था। फिर एक मई की शाम को उसने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। सलमान घर का इकलौता सहारा था। सिलाई का काम करता था और 6 बहनों, 2 भाइयों और बूढ़े मां-बाप की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। सलमान को दफनाने के लिए भी पिता को उधार लेना पड़ा था। इस प्रकरण को लेकर समाजसेवी महेश पांडेय ने कहा कि सलमान बेकसूर था। सिर्फ एक प्रेम प्रसंग में दोस्त की मदद करने के शक में उसे थाने बुलाकर थर्ड डिग्री देना और जेल भेजने की धमकी देना अमानवीय है। मैंने इस मामले को एनएचआरसी में उठाया और आयोग ने इसे गंभीर माना है। **आखिर कौन हैं महेश पांडेय** जयशंकर पटवा फर्जी मुठभेड़ मामला (2009) महेश पांडेय ने कथित फर्जी एनकाउंटर में पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। लम्बी कानूनी लड़ाई के बाद दोषी पुलिसकर्मियों को सजा भी मिली थी। **दीपक यादव पुलिस अभिरक्षा मौत मामला (2016)** बरेली कोतवाली में दीपक यादव की मौत हुई थी। महेश पांडेय की पैरवी पर तत्कालीन कोतवाल वीरेंद्र यादव समेत कई पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज हुआ था।महेश पांडेय बताते हैं कि मैंने पहले भी बेकसूरों के लिए लड़ाई लड़ी है। सलमान का केस भी बिल्कुल वैसा ही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने महेश पांडेय की शिकायत पर केस दर्ज करते हुए कहा है कि यह मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। आयोग ने यूपी पुलिस और बरेली प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। आयोग की इस कार्रवाई से अब यह मामला प्रदेशभर में चर्चा का विषय बन गया है। सलमान की मौत ने बरेली पुलिस की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अब दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी क्या सलमान को न्याय मिलेगा ऐसे ही कई सवाल अब राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने लगे हैं।

Social News Network

NHRC seeks report from Haryana over death of two students at Ashoka University

Posted By: Gopi May 26, 2025

https://www.socialnews.xyz/2025/05/26/nhrc-seeks-report-from-haryana-over-death-of-two-students-at-ashoka-university/

New Delhi, May 26 (SocialNews.XYZ) The NHRC on Monday sought a report from the Haryana government and the state police chief over the death of two students at Ashoka University in Sonipat under suspicious circumstances in February.

A Bench headed by Priyank Kanoongo, taking cognisance of a complaint, directed the government and the police to file an Action Taken Report by June 7.

“Prima facie, the complaint alleges serious human rights violations, potentially stemming from foul play, negligence, or systemic problems such as ragging or academic pressure,” said Kanoongo in the order.

The complainant alleged that the tragic deaths of two University students, on February 14 and 15, raised grave concerns regarding potential institutional lapses.

According to reports, one student is believed to have died by suicide, while another student's body was discovered under unexplained and suspicious circumstances near the private university’s gate just hours later.

“The complainant underscored a troubling lack of transparency surrounding the incidents, including the non-disclosure of the contents of the alleged suicide note. Furthermore, there were critical unanswered questions related to the university's mental health support systems, safety protocols, and the overall campus environment,” noted the NHRC order.

The complainant sought an independent investigation to determine if foul play, negligence, or systemic issues like ragging, academic pressure, or security lapses contributed to the deaths.

The complainant also requested a forensic examination of evidence and demanded accountability at all institutional levels. “If negligence is proven, the complainant urged compensation for families and institutional reforms to prevent future tragedies,” said the NHRC order.

Kanoongo said, “Given that the matter is of a cognizable nature, the National Human Rights Commission has taken cognizance u/s 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993 and directs the Secretary, Higher Education Department, Govt. of Haryana and to the Director General of Police, Haryana, to get the allegations made in the complaint inquire into and to submit an Action Taken Report on or before June 7, 2025, for perusal of the Commission.”

“You are also directed to submit the following documents: a copy of the inquest report, a detailed report of the investigation conducted to date, the post-mortem report (PMR), and all statements recorded by the police during the investigation, including those of family members, friends, and university staff,” said the NHRC order.

Source: IANS

Yes Punjab News

NHRC seeks report from Haryana over death of two students at Ashoka University

https://yespunjab.com/nhrc-seeks-report-from-haryana-over-death-of-two-students-at-ashoka-university/

New Delhi, May 26, 2025

The NHRC on Monday sought a report from the Haryana government and the state police chief over the death of two students at Ashoka University in Sonipat under suspicious circumstances in February.

A Bench headed by Priyank Kanoongo, taking cognisance of a complaint, directed the government and the police to file an Action Taken Report by June 7.

“Prima facie, the complaint alleges serious human rights violations, potentially stemming from foul play, negligence, or systemic problems such as ragging or academic pressure,” said Kanoongo in the order.

The complainant alleged that the tragic deaths of two University students, on February 14 and 15, raised grave concerns regarding potential institutional lapses.

According to reports, one student is believed to have died by suicide, while another student’s body was discovered under unexplained and suspicious circumstances near the private university’s gate just hours later.

“The complainant underscored a troubling lack of transparency surrounding the incidents, including the non-disclosure of the contents of the alleged suicide note. Furthermore, there were critical unanswered questions related to the university’s mental health support systems, safety protocols, and the overall campus environment,” noted the NHRC order.

The complainant sought an independent investigation to determine if foul play, negligence, or systemic issues like ragging, academic pressure, or security lapses contributed to the deaths.

The complainant also requested a forensic examination of evidence and demanded accountability at all institutional levels. “If negligence is proven, the complainant urged compensation for families and institutional reforms to prevent future tragedies,” said the NHRC order.

Kanoongo said, “Given that the matter is of a cognizable nature, the National Human Rights Commission has taken cognizance u/s 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993 and directs the Secretary, Higher Education Department, Govt. of Haryana and to the Director General of Police, Haryana, to get the allegations made in the complaint inquire into and to submit an Action Taken Report on or before June 7, 2025, for perusal of the Commission.”

“You are also directed to submit the following documents: a copy of the inquest report, a detailed report of the investigation conducted to date, the post-mortem report (PMR), and all statements recorded by the police during the investigation, including those of family members, friends, and university staff,” said the NHRC order.(Agency)

Dainik Bhaskar Hindi

शिक्षा: हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी में दो छात्रों की मौत पर एनएचआरसी ने मांगी रिपोर्ट

https://www.bhaskarhindi.com/other/indian-national-human-rights-commission-nhrc-1145574

26 May 2025 8:15 PM

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी में इस साल फरवरी में दो छात्रों की मौत के मामले में संज्ञान लेते हुए विश्वविद्यालय और राज्य पुलिस को जांच करने का आदेश दिया है। साथ ही दोनों से 12 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है।

नई दिल्ली, 26 मई (आईएएनएस)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी में इस साल फरवरी में दो छात्रों की मौत के मामले में संज्ञान लेते हुए विश्वविद्यालय और राज्य पुलिस को जांच करने का आदेश दिया है। साथ ही दोनों से 12 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी गई है।

दोनों छात्रों की मौतों को लेकर उठाए गए गंभीर सवाल और जांच में पारदर्शिता की कमी की शिकायत मिलने के बाद आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सोमवार को इस मामले में नोटिस जारी किया है। इसमें एक छात्र की मौत 14 फरवरी को हुई थी, जिसने कथित तौर पर आत्महत्या की थी। इसके कुछ ही घंटे बाद 15 फरवरी को यूनिवर्सिटी के गेट के पास एक अन्य छात्र का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ था।

शिकायतकर्ता ने पारदर्शिता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मृतक के सुसाइड नोट के कंटेंट को छिपाया गया है। उसने अलग से इस बात की जांच की मांग की कि कहीं दोनों मौतों के पीछे कोई साजिश, लापरवाही या रैगिंग और पढ़ाई का दबाव जैसे नियमित कारक की भूमिका तो नहीं थी।

एनएचआरसी ने अपने नोट में कहा है कि प्रथम दृष्टया शिकायत में मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर मामले उठाए गए हैं।

आयोग ने हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव और हरियाणा पुलिस के महानिदेशक को नोटिस जारी कर मामले की जांच का आदेश दिया है। साथ ही दोनों से 7 जून तक कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) दाखिल करने के लिए भी कहा गया है।

आयोग ने दोनों मामलों में पुलिस द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के दौरान लिए गए सभी बयानों की कॉपी भी मांगी है। इसमें दोनों छात्रों के परिवारों के सदस्यों, दोस्तों और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बयान की प्रति भी मांगी गई है।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Daily Excelsior

Kashmiri Pandits are victims of genocide: PK

https://www.dailyexcelsior.com/kashmiri-pandits-are-victims-of-genocide-pk/

By Daily Excelsior - May 27, 2025

Excelsior Correspondent

JAMMU, May 26: Panun Kashmir (PK), an organisation of Kashmiri Pandits fighting for separate homeland for the community in Kashmir Valley on North East of river Jhelum and demanding that Kashmiri Pandits be declared as victims of genocide through a law enacted by Parliament, has decided to launch a massive campaign for the same across country.

In this regard a major initiative has been taken by PK to build scholarly understanding and intellectual capacity among youth as Panun Kashmir (Yuva) has sponsored 15 of its members to undertake a specialised course in Genocide Studies offered by the Jonaraja Institute of Genocide and Atrocities Studies (JIGAS).

The announcement was made by Chestha Bakshi, Coordinator of Panun Kashmir (Yuva) here who said this was possible with the motivational and inspirational campaigning and vision of PK leaders led by Dr. Ajay Chrungoo, its Chairman. “This is a crucial step in preparing our youth to understand and articulate the genocidal experience of our community through a rigorous academic lens,” said Chestha Bakshi.

While the Jonaraja Institute has emerged as a respected centre for Indic and global genocide studies, notably, many of its alumni now teach in prestigious international institutions, making significant contributions to the field of genocide research.

The course aims to familiarize participants with global genocide frameworks while rooting their understanding in the civilizational experiences and historical memory of the Kashmiri Hindu community. This effort is seen as part of a long-term strategy to cultivate a new generation of youth leaders equipped with scholarly tools to assert the truth of Kashmiri Hindu genocide in academic and policy-making arenas across the world.

It may be recalled that PK has outrightly rejected the term migration affixed with Kashmiri Pandits who were forced to flee from Kashmir in early nineties and termed it a genocide perpetuated by Jihadi elements and Pakistan. They said that Jehadis on behest of Pakistan were responsible of ethenic cleansing of Hindus from Kashmir as well as higher reaches of Jammu region under Dixon plan.

In support of their argument they quoted the **National Human Rights Commission** ruling which has termed the mass exodus of Kashmiri Hindus akin to genocide and urged the Government of India that the community be declared as victims of genocide and it’s perpetrators be identified and punished under law of the land.